



PRASHANTH NARAYAN
 VP & Head - PMS Investments
 ING Investment Management India

Conflicts In 2011

Global upheavals do influence a nation's economy. But at present, India is experiencing some entirely different trends from the ones prevailing in world markets. Read on for the possible conflicts in 2011 in the backdrop of this scenario vis-à-vis the Indian economy

2011 seems to be a year of contrary thoughts. On the one hand, the global economy seems to be shaping up better than expected and this global recovery seems to be adding some risks to the domestic markets. The global economy and the US in particular are showing stronger signs of sustained recovery. On the other hand, quantitative easing as well as expectations of better global economic growth is pushing the inflation higher, especially via higher oil prices, in emerging markets and especially India. This structural inflation risk and a better global economic growth might lead to partial money flow out of emerging economies and into developed economies.

However, real indicators such as employment and retail sales have not yet improved significantly for the US and the euro area. Unemployment in the USA is stubbornly high and any pretense of the Fed being concerned about the dollar's exchange rate has disappeared. In fact, the US authorities in general are unaware or do not care that a weaker currency leads to imported inflation.

The Euro economy still continues to remain on a slippery slope. European sovereign debt crisis will probably continue to be negative, despite efforts from the EU region to contain the sequence of fiscal crisis the European economies are facing. In both the UK and the Euro zone, inflation has risen over the target ceiling rate of 2 per cent, especially in the UK and all logic says that a rise in rates is likely in 2011, led by the BoE. US FED will probably be the last to follow this chain of interest rate increases.

The Indian economy in itself is facing the opposing trends. The economic growth has been healthy and might continue to grow at a pace of 8 per cent in FY12. However, there are short-term resistances, which, if not managed, can become structural. First such issue is the balance between liquidity/interest rates and the structural inflation. We have always noted that the inflation India is facing is structural due to rising global commodity prices and excess global liquidity due to quantitative easing. The second such issue is the lack of capital goods formation in the country primarily owing to a lack of clarity in policy and execution. Recent issues in corporate governance will act as a short-term drag for foreign fund flows.

Despite these resistances, given the state of the global economy, Indian economic growth is healthier and robust as compared to its emerging market peer group. Domestic consumption is growing at a very healthy rate and is more than ever supported by growth in the rural India. We also anticipate that capital expenditure might gradually increase over this year but might face policy-related resistance.

Gold and precious metals might face some resistance given that the confidence in the global economic growth is slowly increasing, however the waning impact of US QE2 and the EU area risks will provide a support for gold. On the rates front, tight liquidity still continues with the central bank coming up with measures to ease the liquidity situation with Open Market Operations (OMOs) of ₹48,000 crore and reduced the SLR by 1 per cent.

GOLD MAY LOSE SHINE

Gold and precious metals might face some resistance with an increase in global economic growth.

RISE IN INFLATION

Quantitative easing and expectations of better global economic growth is pushing the inflation up, via higher oil prices, in emerging markets like India.

(As told to Dalal Street Investment Journal. The magazine may or may not subscribe to the views expressed in the article. Wish to comment on this article? Send your feedback to comment@dsij.in)

2011 में अंतर्विरोध

ग्लोबल घटनाएं एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं. पर इस समय भारत विश्व मार्केट में मौजूद ट्रेंड से बिल्कुल अलग ही ट्रेंड के दौर से गुजर रहा है. इस तरह ग्लोबल परिदृश्य और भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच 2011 में कई अंतर्विरोध हैं

वर्ष 2011 की शुरुआत अंतर्विरोधी विचारों का साथ हुई है. एक ओर ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अपेक्षा से कहीं बेहतर सुधार हो रहा है और वहीं यह ग्लोबल रिकवरी घरेलू मार्केट में जोखिम बढ़ा रही है. ग्लोबल अर्थव्यवस्था और विशेषकर अमेरिका में लगातार अच्छी रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं. दूसरी ओर क्वांटिटेटिव ईजिंग और ग्लोबल अर्थव्यवस्था से बेहतर उम्मीदें मुद्रास्फीति को बढ़ा रही हैं विशेषकर उभरते बाजारों और खासकर भारत में कच्चे तेल के भाव काफी बढ़ गए हैं. इस तरह मुद्रास्फीति की जोखिम और बेहतर ग्लोबल आर्थिक परिदृश्य से हो सकता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पैसा विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर जाये.

पर वास्तविक संकेतक जैसे कि रोजगार और रिटेल बिक्री में अभी तक अमेरिका व यूरोपीय देशों में अधिक वृद्धि नहीं नजर आ रही है. अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर अभी भी काफी

ऊपर है और फेड डॉलर के एक्सचेंज रेट को लेकर बहुत अधिक चिंतित नहीं है. वास्तव में अमेरिकी प्रशासन कमजोर करेंसी को बहुत अधिक महत्व नहीं दे रहा है जो आयात मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं.

यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है. यूरोपीय डेब्ट संकट लगता है कि अभी भी काफी समय तक संकट की स्थिति बनाए रखेगा. हालांकि इस क्षेत्र में यूरोपीय देश काफी प्रयासरत हैं. इंग्लैंड और यूरोजोन दोनों में ही मुद्रास्फीति दो प्रतिशत से अधिक हो चली है विशेषकर इंग्लैंड में. इस साल इस दिशा में रेट बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है. ऐसा लगता है कि ब्याज दरों में वृद्धि करने की दिशा में अमेरिकी फेड भी अंत में सक्रिय होगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरे संकट झेल रही है. एक ओर जहां आर्थिक ग्रोथ अच्छी है और संभवतः वित्तवर्ष 12 में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखेगी वहीं शार्ट टर्म के प्रतिरोध भी नजर आ रहे हैं जिनका

यदि उचित प्रबंध न किया गया तो उन्हें गहरा भी सकते हैं. इसमें पहला मुद्दा है लिक्विडिटी और ब्याज दरों में समन्वय बनाए रखना. हमने देखा है कि भारत में मुद्रास्फीति ग्लोबल स्तर पर कमांडिटी के प्राइस बढ़ने के कारण है और इस



प्रशांत नारायण
वीपी व हेड - पीएमएस इन्वेस्टमेंट्स
आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट

पर ग्लोबल लिक्विडिटी की अधिकता का असर है. दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि देश में पूंजीगत वस्तुओं का अभाव है क्योंकि इस दिशा में नीतियां बहुत स्पष्ट नहीं हैं. पिछले दिनों कारपोरेट गवर्नेंस को लेकर उठा सवाल विदेशी फंडों की आवक पर शार्ट टर्म में असर डाल सकता है.

फिर भी तमाम गतिरोधों के बावजूद ग्लोबल अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बहुत अच्छा कहा जा सकता है. इतना ही नहीं उभरते बाजारों की तुलना में इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है. यहां घरेलू खपत में बहुत अच्छी दर पर बढ़त हो रही है और इसे ग्रामीण भारत का समर्थन मिल रहा है. हमें लगता है कि पूंजीगत खर्च भी इस साल धीरे-धीरे बढ़ेंगे पर यह भी संभव है कि नीतिगत मुद्दे इस पर लगाम लगायें.

गोल्ड आदि मेटल को प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है क्योंकि ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ में विश्वास धीरे-धीरे बढ़ रहा है. फिर भी अमेरिकी क्वांटिटेटिव ईजिंग और यूरोपीय संघ के देशों की जोखिम गोल्ड को समर्थन प्रदान करेगी. जहां तक दरों की बात है तो लिक्विडिटी की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है.

(लेखक के विचारों से दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)